

दल-बदल में स्पीकर की भूमिका

प्रलिस के लयः

दल-बदल वरिधी कानून, 10वीं अनुसूची, अखलि भारतीय पीठासीन अधकारियों का सम्मेलन, 1985 में 52वाँ संशोधन, 91वाँ संवैधानकि संशोधन अधनियम, 2003, न्यायकि समीक्षा ।

मेन्स के लयः

दल-बदल हेतु आधार, दल-बदल में अध्यक्ष की भूमिका ।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने 15 फरवरी, 2023 को महाराष्ट्र संकट 2022 से संबंधित एक मामले और क्या स्वयं नषिकासन के नोटसि का सामना कर रहा स्पीकर/अध्यक्ष अपनी वधिनसभा में वधायकों को अयोग्य घोषति कर सकता है, पर सुनवाई करते हुक्हा कि [अयोग्यता पर फैसला लेने हेतु स्पीकर को पहला अधिकार होना चाहयि](#) ।

- इससे पहले वर्ष 2016 में नबाम रेबया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नषिकासन के नोटसि का सामना करने वाला अध्यक्ष या [उपाध्यक्ष](#) वधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही तय नहीं कर सकता है ।

अध्यक्ष की भूमिका पर वाद-ववादः

- पछिले तीन वर्षों से [लोकसभा अध्यक्ष](#) की अध्यक्षता में अखलि भारतीय पीठासीन अधकारियों का सम्मेलन [संवधान की 10वीं अनुसूची](#) में वर्णति अध्यक्ष की भूमिका की समीक्षा कर रहा है, जो सांसदों और वधायकों की अयोग्यता से संबंधति है ।
- चर्चाओं का मुख्य केंद्रबंदि इस मामले में वधिनसभा स्पीकर की गरमा को सुरक्षति करना है । कई पीठासीन अधकारियों ने वचिर व्यक्त कया है कि उसकी भूमिका सीमति होनी चाहयि और दल-बदल के मामलों को तय करने हेतु अन्य तंत्र वकिसति कया जाना चाहयि ।
- एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है कि [अयोग्यता के मुद्दे को संबंधति राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया](#) जाए क्योंकि वधायकों को टिकट देते हैं ।
- वर्ष 2021 में देहरादून में अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान कई प्रतभागियों ने अपनी चतिओं को व्यक्त कया और उन कमयों की ओर इशारा कया जो अक्सर अध्यक्ष की भूमिका को प्रभावति करती हैं ।

भारतीय संवधान की 10वीं अनुसूचीः

- परचयः**
 - भारतीय संवधान की 10वीं अनुसूची, जसि [दलबदल वरिधी कानून](#) के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संवधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ।
 - यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद दल-बदलने वाले वधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गरिने की प्रतिक्रया थी ।
 - यह दल-बदल के आधार पर संसद (सांसदों) और राज्य वधिनसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधति प्रावधानों को नरिधारति करता है ।
- अपवादः**
 - यह सांसद/वधायकों के एक समूह को दल-बदल हेतु दंडति कयि बना कसि अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (यानी वलिय) की अनुमति देता है ।
 - और यह दल बदलने वाले वधायकों को प्रोत्साहति करने या स्वीकार करने के लयि राजनीतिक दलों को दंडति नहीं करता है ।
 - वर्ष 1985 के अधनियम के अनुसार, [कसि राजनीतिक दल के नरिवाचति सदस्यों में से एक-तहाई द्वारा 'दलबदल' को 'वलिय' माना जाता था](#) ।
 - [91वें संवधान संशोधन अधनियम, 2003](#) ने इसे बदल दिया और अब कसि दल के कम- से-कम दो-तहाई सदस्यों को "वलिय" के पक्ष में होना चाहयि ताकि कानून की नज़र में इसकी वैधता हो ।

■ **वविकाधकार:**

- दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर नरिणय सदन के सभापतया अध्यक्ष द्वारा लया जाता है, जो **'न्यायकि समीक्षा'** के अधीन है ।
- हालाँकि कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामले का फैसला करना होता है ।

■ **दल-बदल का आधार:**

- यदकि कोई **नरिवाचति सदस्य सवेच्छा से कसिी राजनीतकि दल की सदस्यता छोड देता है ।**
- यदविह अपने राजनीतकि दल द्वारा जारी कसिी नरिदेश के वपिरीत सदन में **मतदान** करता/करती है या मतदान से **दूर रहता/रहती** है ।
- यदकि कोई **सवतंत्र रूप से नरिवाचति सदस्य** कसिी राजनीतकि दल में शामिल होता है ।
- यदकि कोई **नामति सदस्य** छह माह की समाप्तके बाद **कसिी राजनीतकि दल में शामिल** होता है ।

नषिकरष:

दल-बदल के मामलों में अध्यक्ष की भूमिका सरकार और लोकतांत्रकि प्रणाली की स्थरिता एवं अखंडता सुनश्चिति करने के लयि महत्त्वपूर्ण है । यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अध्यक्ष को ऐसे मामलों पर नरिणय लेते समय नषिपक्ष तरीके से कार्य करना होता है तथा नरिणय प्राकृतकि न्याय के सिद्धांतों व संवधान के प्रावधानों द्वारा नरिदेशति होना चाहयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संवधान की नमिनलखिति में से कसि अनुसूची में दल-बदल वरिधी प्रावधान हैं? (2014)

- (a) दूसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) आठवी अनुसूची
- (d) दसवी अनुसूची

उत्तर: (d)

स्रोत: हदिसतान टाइम्स

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/speaker-s-role-in-defection>